



6 March, 2024

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

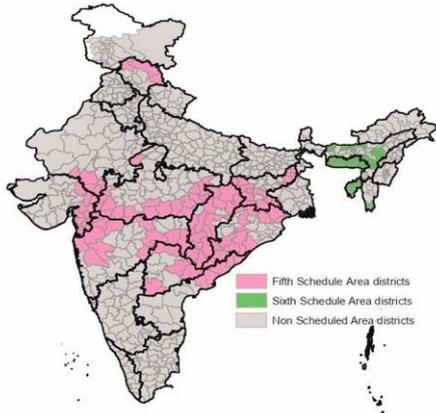
संदर्भ: हाल ही में झारखंड में पेसा कार्यान्वयन को बढ़ाने पर दूसरा दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन की मुख्य बातें:

- PESA अधिनियम को सुदृढ़ करने और प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- विगत 4-5 मार्च, 2024 को आयोजित इस सम्मेलन ने उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी और व्यावहारिक योगदान से अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया।
- PESA के सफल कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण गति प्राप्त हुई है, जिससे इसके कार्यान्वयन में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्य बातें:

- **गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका:** गैर-सरकारी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से PESA कार्यान्वयन को आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।
- **वन अधिकार अधिनियम का प्रवर्तन:** ज्ञान-साझाकरण को सुविधाजनक बनाने और PESA उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए PESA क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम को लागू करने पर विशेष चर्चा की गई।
- **केस स्टडीज और सफलता की कहानियाँ:** विभिन्न क्षेत्रों में की गई केस स्टडीज और उनके सफलता की कहानियों द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा और मार्गदर्शन, प्रतिभागियों को अपने स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ने में सहायता करती है।



पेसा अधिनियम 1996 का अवलोकन:

- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज प्रावधानों का विस्तार करने के लिए दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया।
- ग्राम सभा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना।
- वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों में लागू है, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि शामिल हैं।

पेसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य:

- संशोधनों के साथ पंचायती राज प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार।
- आदिवासी आबादी के लिए स्वशासन की स्थापना।
- सभी गतिविधियों के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाना।
- पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप प्रशासनिक संरचनाओं का विकास।
- जनजातीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण।
- जनजातीय समुदायों के लिए लाभकारी विशिष्ट शक्तियों के साथ पंचायतों का सशक्तिकरण।
- उच्च-स्तरीय पंचायतों पर ग्राम सभा के अधिकार का संरक्षण।

पेसा अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताएं:

- अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य विधान को जनजातीय प्रथागत कानूनों और परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रत्येक गाँव अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार सामुदायिक मामलों का प्रबंधन करते हैं।
- प्रत्येक ग्राम सभा पात्र ग्रामीणों की एक मतदाता सूची रखती है।
- ग्राम सभा विकास योजनाओं को मंजूरी देने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है।
- पंचायतों में निधि उपयोग के लिए ग्राम सभा से प्रमाणीकरण आवश्यक है।
- जनजातीय आबादी के अनुपात में पंचायतों में सीटों का आरक्षण किया जाता है।
- गौण खनिज दोहन की रियायत के लिए अनिवार्य ग्राम सभा की सिफारिश की जाती है।

पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- इस अधिनियम में संदर्भित कानूनी कठिनाइयों में अस्पष्ट परिभाषाएँ और मौजूदा कानूनों के साथ टकराव शामिल हैं।
- इसमें राजनीतिक चुनौतियाँ स्वार्थ और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से उत्पन्न होती हैं।

पेसा अधिनियम के भविष्य के निहितार्थ:

- यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाता है।
- यह शासन और राष्ट्र निर्माण के साथ जनजातीय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है।
- यह आदिवासी अधिकारों की ऐतिहासिक उपेक्षा को संबोधित करता है।
- यह कार्यान्वयन चुनौतियों और खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से टोस कार्रवाई की माँग करता है।

चुनाव के लिए GenAI को सरकार का परामर्श

संदर्भ: केंद्र सरकार द्वारा आगामी चुनावों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम का उपयोग करने वाले सभी मध्यस्थों और एआई प्लेटफार्मों को एक परामर्श दिया गया है।

एआई सिस्टम पर सरकारी परामर्श:

- भारतीय उपयोगकर्ताओं को कम परीक्षण वाले या अविश्वसनीय एआई सिस्टम या बड़े भाषा मॉडल (LLM) की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों को तैनाती से पहले केंद्र से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- उन्हें उत्पन्न आउटपुट की संभावित गिरावट या अविश्वसनीयता को भी चिन्हित करना आवश्यक होगा।
- गलत सूचना या डीपफेक के प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने के लिए एक ट्रैसेबिलिटी आवश्यकता को जोड़ा जाना चाहिए।

सरकारी परामर्श की मुख्य बातें:

- उपयोगकर्ताओं को संभावित गिरावट के बारे में सूचित करने के लिए निर्माता (उत्पादक/ प्रवर्तक) एआई आउटपुट को चिन्हित किया जाना चाहिए।
- गलत सूचना या डीपफेक के निर्माता या प्रवर्तक का पता लगाने के लिए एआई-जनित सामग्री में अद्वितीय मेटाडेटा या पहचानकर्ताओं को सहेखित किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त सभी एआई प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके कंप्यूटर संसाधन चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता न करें।

चुनावी निष्ठा पर ध्यान दें:

- आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस सरकारी परामर्श में चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
- इस संदर्भ में गलत सूचना और डीपफेक को चुनाव परिणामों को प्रभावित करने से रोकने के लिए एआई उत्पाद लॉन्च में कठोरता और जांच की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

Face to Face Centres





6 March, 2024

➤ जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:

- **परिभाषा:** जेनेरेटिव/प्रवर्तक एआई में गहन-शिक्षण मॉडल शामिल हैं, जो मूल डेटा इनपुट से सांख्यिकीय रूप से संभावित आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं।
- **फाउंडेशन मॉडल:** ये एआई मॉडल, जिन्हें फाउंडेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है, बड़े होते हैं और बहुआयामी कार्यों को करने में सक्षम हैं। साथ ही यह संक्षेपण, प्रश्न उत्तर और वर्गीकरण जैसे कार्य भी करते हैं।
- **अनुकूलनशीलता:** फाउंडेशन मॉडल को न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसे कम डेटा के साथ विशिष्ट उपयोग हेतु अनुकूलित भी किया जा सकता है।
- **जेनेरेटिव एआई की कार्यप्रणाली:**
 - **मशीन लर्निंग मॉडल:** जेनेरेटिव एआई मानव-निर्मित डेटासेट के भीतर पैटर्न और संबंधों को समझने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करता है।
 - **सामग्री निर्माण:** मशीन लर्निंग तकनीक के आधार पर, एआई नई कंटेंट सामग्री उत्पन्न करता है, जो विभिन्न डेटासेट के साथ संरेखित होती है।
 - **प्रशिक्षण दृष्टिकोण:** सामान्य प्रशिक्षण पद्धति में पर्यवेक्षित शिक्षण शामिल होता है, जहां मॉडल मानव-निर्मित सामग्री और संबंधित लेबल के एक सेट से सीखता है।
- **जेनेरेटिव एआई के अनुप्रयोग:**
 - **उन्नत ग्राहक संपर्क:** जेनेरेटिव एआई ग्राहक इंटरैक्शन को बढ़ाते हुए चैट और खोज अनुभवों को बेहतर बनाता है।
 - **डेटा अन्वेषण:** यह संवादात्मक इंटरफेस और सारांश के माध्यम से बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा को नेविगेट करने में सहायता करता है।
 - **कार्य स्वचालन:** जेनेरेटिव एआई विभिन्न प्रस्तावों का जवाब देने, विपणन सामग्री को स्थानीयकृत करने और अनुपालन के लिए ग्राहक अनुबंधों की जांच करने जैसे दोहराव वाले कार्यों को भी संभालता है।

➤ वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं के 190 क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों का विश्लेषण किया जा रहा है।
- विश्व बैंक समूह की इस नई रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार पहले के अनुमान से कम हैं।
- महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों का दो-तिहाई (64%) से भी कम अधिकार प्राप्त है, जो पहले की अपेक्षा 77% से कम है।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक की वृद्धि हो सकती है, जिससे अगले दशक में वैश्विक विकास दर दोगुनी हो सकती है।

➤ सूचकांक माप:

- इस संबंध में जारी रिपोर्ट सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, बच्चे की देखभाल, उद्यमशीलता, संपत्ति और पेंशन सहित दस संकेतकों में कानूनी ढांचे का आकलन करती है।
- इसमें हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुंच को महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उजागर किया गया है।

➤ भारत का प्रदर्शन:

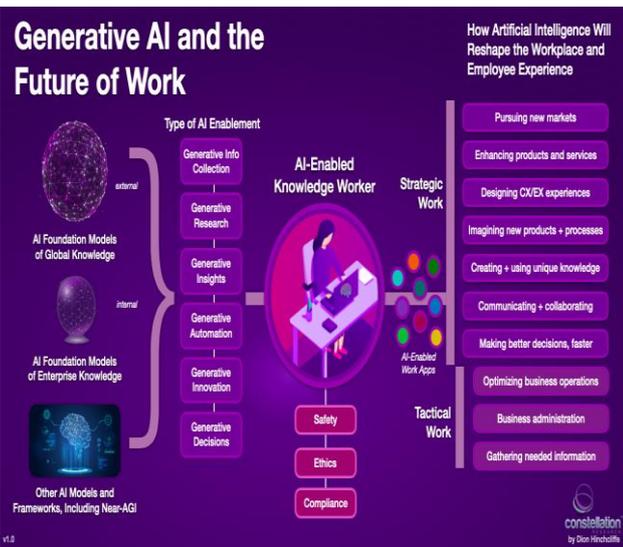
- 74.4% के स्कोर के साथ भारत की रैंक मामूली सुधार के साथ 113 हो गई है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है।
- भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 60% कानूनी अधिकार हैं, जो वैश्विक औसत 64.2% से थोड़ा कम है।
- भारत ने दक्षिण एशियाई समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है, विशेषकर आवाजाही और विवाह की स्वतंत्रता पर बाधाओं के मामले में।

➤ भारत के लिए सिफारिशें:

- भारत समान काम के लिए समान वेतन को अनिवार्य करके और महिलाओं को रात में काम करने एवं पुरुषों के साथ समान स्तर पर औद्योगिक नौकरियों में संलग्न होने में सक्षम बनाकर महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार कर सकता है।
- चाइल्डकैरर प्रदाताओं की सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्ट्री बनाने और एक अच्छी तरह से परिभाषित आवेदन प्रक्रिया को लागू करने सहित चाइल्डकैरर ढांचे को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की जाती है।

➤ वैश्विक अंतराल:

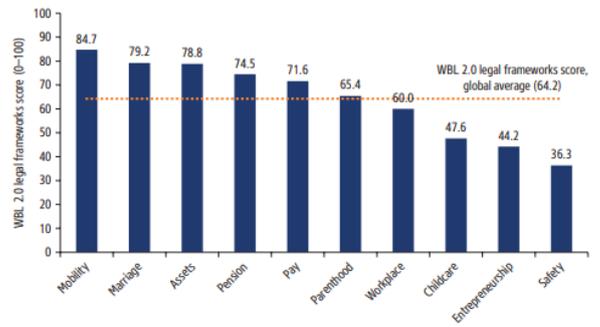
- विश्व स्तर पर, यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करती है।
- महिलाओं के लिए समान वेतन अनिवार्य करने वाले कानून बनाने के बावजूद, केवल कुछ देशों ने वेतन अंतर को समाप्त करने के उपाय अपनाए हैं।



महिलाएँ, व्यवसाय और तत्संबंधी कानून, 2024

संदर्भ: विश्व बैंक ने हाल ही में उन बाधाओं का विश्लेषण किया जो महिलाओं को वैश्विक कार्यबल में प्रवेश करने से रोकती हैं, जिससे उनकी स्वयं की, अपने परिवार और अपने समुदायों की समृद्धि में योगदान करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

FIGURE ES.3 | SAFETY, ENTREPRENEURSHIP, AND CHILDCARE INDICATORS HAVE THE LARGEST LEGAL GAPS



Source: Women, Business and the Law 2024 database.
Note: WBL = Women, Business and the Law.

WBL indicator

Face to Face Centres





NEWS IN BETWEEN THE LINES

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार



आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति 2022 और 2023 दोनों वर्षों के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कारों के अलावा, राष्ट्रपति सात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (अकादमी रत्न) से भी सम्मानित करेंगी।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में:

- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे 1952 से प्रदान किया जा रहा है।
- यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कलाओं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला रूपों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाता है।
- इसमें एक लाख रुपये की राशि, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है।
- अकादमी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (1959), जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी (1954), कथक केंद्र (1964) सहित प्रदर्शन कलाओं में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों और परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और कुटियाट्टम, छऊ नृत्यों और सत्रिया परंपराओं जैसी परियोजनाओं का समर्थन करती है।

संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप:

- संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (अकादमी रत्न) प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रख्यात कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, जो किसी भी समय केवल 40 कलाकारों को ही दिया जा सकता है।
- अकादमी फेलो सम्मान के साथ तीन लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी



हाल ही में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बेंगलुरु लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जेल कठोरपंथीकरण मामले में अपनी जांच के तहत सात राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारत की आतंकवाद से निपटने वाली प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 2008 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी।
- यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा देने वाले किसी भी अपराध की जांच के लिए जिम्मेदार है।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विशेष अदालतें स्थापित करने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम उन परीक्षणों के लिए विशेष प्रक्रियाएं भी बनाता है जो दंड प्रक्रिया संहिता पर सामान्य कानून से भिन्न होती हैं।

भारतीय फार्माकोपिया



हाल ही में, निकारागुआ सैनिक बोलने वाली दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है जिसने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दी है।

भारतीय फार्माकोपिया के बारे में:

- इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) भारत में दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक है जिसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
- यह भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसे अब तक पाँच देशों: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम द्वारा मानक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारत में आयात, निर्मित और वितरित की जाने वाली सभी दवाओं को भारतीय फार्माकोपिया में संहिताबद्ध मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा



भारत के प्रधानमंत्री आज कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे।

के बारे में:

- नई मेट्रो लाइन, जिसे हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड कहा जाता है किसी प्रमुख नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग होगी।
- यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है जो कोलकाता और हावड़ा शहरों को इसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर अलग करती है।
- इस नई लाइन का हिस्सा हावड़ा मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने का गौरव प्राप्त करेगा।
- हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का दूसरा खंड बनाता है जो हावड़ा मैदान को आईटी हब साल्ट लेक सेक्टर -5 से जोड़ता है।
- ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के 16.6 किलोमीटर में से 10.8 किलोमीटर में हावड़ा मैदान और फूलबागान के बीच एक भूमिगत गलियारा शामिल है जिसमें हुगली नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है जबकि शेष हिस्सा ऊंचा है।
- इस परियोजना को एक चमत्कार करार दिया गया है जिसमें ट्रेनों नदी की सतह से लगभग 16 मीटर नीचे यात्रा करती हैं।

Face to Face Centres





6 March, 2024

सुर्खियों में स्थल

फ्रांस

हाल ही में, फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया है।

फ्रांस (राजधानी: पेरिस)

अवस्थिति : फ्रांस, आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी गणराज्य, पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है।

भौगोलिक सीमाएँ:

फ्रांस की सीमा स्विट्जरलैंड (पूर्व), अटलांटिक महासागर (पश्चिम), बेल्जियम, लक्जमबर्ग और उत्तरी सागर (उत्तर), जर्मनी (उत्तरपूर्व), इटली, मोनाको और भूमध्य सागर (दक्षिणपूर्व), अंडोरा और स्पेन (दक्षिण), इंग्लिश चैनल (उत्तर पश्चिम) के साथ लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- फ्रांस में सबसे ऊंचा बिंदु मोंट ब्लाँक है जो फ्रेंच आल्प्स में स्थित है।
- फ्रांस की प्रमुख नदियों में सीन, लॉयर, रोन, गैरोन, डॉरदोम्ने, मीयूज, मार्ने और मोसेले शामिल हैं।
- फ्रांस में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में कोयला, लोहे का अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, पोटैश, नमक, सीसा, जस्ता और तांबा शामिल हैं, जो इसके खनिज संसाधन आधार में योगदान करते हैं।

संसदीय प्रणाली:

- फ्रांस में एक द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय सभा (निचला सदन) और सीनेट (ऊपरी सदन) शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य प्रमुख और प्रधान मंत्री सरकार प्रमुख होते हैं।



POINTS TO PONDER

- हाल ही में खबरों में रही अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यार्स मिसाइल किस देश ने विकसित की है? – रूस
- एमएच 60आर सीहॉक क्या है जो हाल ही में खबरों में है? – ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण
- हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति (ADITI) योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? – रक्षा क्षेत्र
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- हाल ही में खबरों में रही इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? – तेलंगाना

Face to Face Centres

